वर्ष 2 अंक 6 जून 1980 50 पैसे

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

सीटू कार्यकर्त्ता की हत्या

फरीदाबाद में बाहमी प्रिंटर्स (प्रा.) लि. के एक ठेकेदार ने मालिकान की शह पर सीटू के कार्यकर्ता कामरेड कंचन की 18 मई को हत्या कर दी. यूनियन के नेताओं को प्रबंधकों के गुंडों द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही थीं और रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद पुलिस अधिकारियों ने कोई सुरक्षात्मक कार्यवाही नहीं की. सीटू की दिल्ली कमेटी ने 21 मई को अपने एक बयान में कहा है है कि सीटू कार्यकर्त्ता की हत्या की साजिश पुलिस को मालूम थी, लेकिन कोई कदम उठाने के बजाए यह मजदूरों को ही आतंकित कर रही है. पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नही की है और वह मामले को रफा-दफा करने की कोशिश कर रही है.

सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी ने दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही और मजदूरों के हित में जान देने वाले मजदूर के आश्रितों को उचित मुआवजा देने की मांग की है.

सीटू की दिल्ली कमेटी के अध्यक्ष चाचा शादी राम ने सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का आह्वान किया है कि वे मजदूरों के खिलाफ प्रबंधकों की गुंडागर्दी के विरोध में एकजुट हों.

बैंक इजारेदारों की मांगें पंच-फैसले के लिए सौंपी गई

बैंक प्रबंधकों की मांगों को पंच फैसले के लिए सौंपना स्वीकार करके आल इंडिया बैंक एंप्लाईज एसोसिएशन (ए. आई. बी. ई. ए.) और नेशनल कनफेडरेशन आफ बैंक एंप्लाईज (एन. सी. बी. ई.) के नेतृत्व ने एक बार फिर बैंक कर्मचारियों को नीचा दिखाया है. बैंक कर्मचारियों की यूनियनों के नेतृत्व के साथ वार्ताओं के दौरान बैंक इजारेदार अपनी मांगों को सौदेबाजी के काउंटर के तौर पर इस्तेमाल करते थे. यह इन प्रबंधकों की बैंक कर्मचारियों को दी गई सुविधाओं को अधिक मशीनीकरण करने व कर्मचारियों का कार्यभार बढ़ाकर खत्म करने की चाल थी.

पिछली सात अप्रैल को एक समझौते पर हस्ताक्षर करके इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की निम्न मांगों को पंच फैसले के लिए सौंपा गया है: 1. ओवरटाइम कार्य की मौजूदा सीमा को कम किया जाना, 2. विशेष भत्ता पानेवाले क्लर्कों की ड्यूटी और जिम्मेदारियों को बढ़ाना, 3. मशीनीकरण या कंप्यूट्राइजेशन में वृद्धि या विस्तार, 4. पदोन्नति नीति, 5. पार्ट टाइम कर्मचारियों की नियुक्ति, 6. 12. 10. 1970 के समझौते में धारा 11 (सी) को हटाना या उसमें संशोधन करना ताकि एक कर्मचारी के सी.सी.ए. कद्र से गैर सी.सी.ए. केंद्र में तबादला होने से सी.सी.ए. को पूरी तरह से तरह से वापस लिया जा सके, 7. ऐसी परिस्थितियों को बनाना जिसमें ड्यूटी से गैरहाजिरी को स्वेच्छा से नौकरी त्यागना माना जाए, 8. उन केसों में जिनमें यात्रा उसी दिन पूरी हो जाए, ठहरने का भत्ता, बट्टा, ओवर टाइम की अदायगी के नियमों में संशोधन और शास्त्री अवार्ड के पैरा 517 के तहत शिकायत-तरीके में संशोधन.

इस प्रकार आई. बी. ए. की ये 9 मांगें ए. आई. बी. ई. ए. की रजामंदी से पंच फैसले के लिए सौंप दी गयी. इसके बदले में प्रबंधकों ने यूनियन की मुअत्तिली के दौरान सबसिस्टैंस भत्ते के देने में वृद्धि करने की मांग को सौंपना स्वीकार किया है. असलियत में प्रबंधकों का 'मांग पत्र' ही पंच फैसले के लिए सौंपा गया है. समझौते में कहा गया है कि "पंच फैसला मुख्य समझौते की पार्टियों पर लागू होगा... और इसे इस प्रकार से लागू किया जाएगा जैसे कि

[शेष पृष्ठ सोलह पर]

अंदर के पृष्ठों में
भारत में बढ़ते औद्योगिक विवाद 6
विकास पर विश्व ट्रेड यूनियन सम्मेलन 8
तीन लाख मजदूर घायल 11
दिल्ली, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि प्रदेशों से समाचार

21 अप्रैल : अखिल भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया

मार्च में नई दिल्ली में सीटू की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी. इस बैठक में आह्वान किया गया कि 21 अप्रैल को अखिल भारतीय मांग दिवस के रूप में मनाया जाए तथा देशभर में सभाएं, प्रदर्शन तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और इनमें मजदूर वर्ग के पांच मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया जाए. ये मुद्दे हैं—अधिनायकवाद का खतरा, आवश्यक वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमतें, बेरोजगारी में बढ़ौतरी, निरंतर बिगड़ते केन्द्र व राज्यों के संबंध तथा भारतीय उपमहाद्वीप में साम्राज्यवादी ताकतों की घुसपैठ. हमारे पत्र ने दिल्ली की रिपोर्ट पिछली बार छापी थी. इस बीच हमें विभिन्न स्थानों से कुछ और रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं जिन्हें संक्षिप्त रूप में यहां छापा जा रहा है.

अहमदाबाद—सारंगपुर से एक जुलूस निकाला गया और टाउन हाल पर सभा का आयोजन किया गया. स्थानीय नगर निगम के कार्यालय के बाहर एक धरने का आयोजन भी किया गया.

बड़ौदा—इंजीनियरिंग मिलों के मजदूरों तथा नगर निगम के कर्मचारियों ने एक आम सभा की.

बिजनौर—चीनी मिलों में एक आम सभा आयोजित की गयी.

बीकानेर—शहर में एक जुलूस निकाला गया जो जिला कलेक्टर के दफ्तर तक आते-आते एक आम सभा के रूप में बदल गया. एक दस-सूत्रीय मांग पत्र भी पेश किया गया.

बुलंदशहर—पन्नीजी शक्कर मिल के मैदान में एक रैली का आयोजन किया गया तथा पर्चे भी बांटे गए.

कलकत्ता—17 अप्रैल को केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों का एक सम्मेलन बुलवाया गया था. इस सम्मेलन में सीटू, एटक, यूटक, टी. यू. सी. सी., सरकारी कर्मचारियों की 12 जुलाई कमेटी संगठनों तथा अन्य मजदूर संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया. इस सम्मेलन में अधिनायकवाद के लगातार बढ़ रहे खतरे, कीमतों में वृद्धि और तीन राज्यों में स्थापित वामपंथी सरकारों को हो रहे खतरे के विरुद्ध एक प्रस्ताव पास किया गया. साथ ही 21 अप्रैल को अधिनायकवादी खतरे और कीमतों में वृद्धि के विरुद्ध प्रदर्शन किए जाने का आह्वान किया. 21अप्रैल को बहुत भारी प्रदर्शन किया गया जो शही मीनार मैदान से शुरू हुआ. हावड़ा 24 परगना और जलपाइगुडी में भी प्रदर्शन किए गए. इन प्रदर्शनों में मजदूरों, किसानों, विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के अतिरिक्त अन्य वर्गों ने भी भाग लिया.

ग्वालियर—विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने एक प्रदर्शन का आयोजन किया जो बाद में एक आम सभा की शक्ल में बदल गया.

गुआ (सिंहभूम, बिहार)—यूनाइटेड मिनरल्स वर्कर्स यूनियन ने एक आम सभा की.

हांसी—अखिल भारतीय दिवस पांच मुख्य मुद्दों के अतिरिक्त आम सभा में स्थानीय मुद्दों पर भी ध्यान आकर्षित किया गया.

हिसार—पृथ्वीसिंह की अध्यक्षता में आयोजित एक आम सभा में अखिल भारतीय दिवस के पांच सूत्रों के संबंध में कई प्रस्ताव पास किए गए और साथ ही हरियाणा सरकार की जन-विरोधी नीतियों पर भी प्रकाश डाला गया.

जमशेदपुर—उद्यान विभाग, टिस्को डेरी और पोलट्री फार्म के मजदूरों ने सुबह प्रदर्शन किया तथा शाम को एक आम सभा का आयोजन किया.

कुइया (बिहार, कोयला क्षेत्र)—कोलियरी मजदूर सभा आफ इंडिया की एक शाखा, कुइया कोलरी ने एक रैली का आयोजन किया जिसमें स्थानीय मांगों पर प्रकाश डाला गया. प्रबंधकर्त्ताओं को एक ज्ञापन भी दिया गया.

नजीबाबाद—चंद्र स्पिनिंग मिलों के द्वार पर एक सभा आयोजित की गई

[शेष पृष्ठ चार पर]

ट्रेड यूनियन नेताओं के कर्नाटक से निष्कासन की सीटू द्वारा भर्त्सना

सीटू के अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने 13 मई को निम्न वक्तव्य जारी किया :

सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंज सीटू की कर्नाटक राज्य कमेटी के अध्यक्ष एस. सूर्यनारायण राव सहित बंगलौर के एम. आई. सी. ओ. (माइको) के अन्य नेताओं को राज्य से निष्कासित किए जाने के कदम की निंदा करती है.

सरकार का यह कदम मजदूरों के ट्रेड यूनियन अधिकारों पर सीधी चोट है. इसका एक उद्देश्य एकाधिकारी संस्थान माइको के प्रबंधकों को सहायता पहुंचाना और बदनाम कर्नाटक पुलिस कानून की सहायता से अपनी उचित मांगों के लिए जारी मजदूर संघर्षों को कुचलना भी है. यह कदम अधिक निन्दनीय इसलिए हो जाता है क्योंकि मजदूरों ने अपने लंबे संघर्ष के बाद हाल ही में सफलता पाई थी.

मायको के प्रबंधक ट्रेड यूनियन के नेताओं के खिलाफ गुंडों का प्रयोग कर रहे हैं और इन गुंडों के विरुद्ध ट्रेड यूनियनों द्वारा लिए गए आत्मरक्षा के हर कदम को पुलिस अधिकारी 'मुठभेड' का नाम देकर प्रबंधकों का पूरा-पूरा सहयोग दे रहे हैं.

सीटू कर्नाटक पुलिस की इन हरकतों को खत्म करने तथा मालिकों के गुंडातत्वों के विरुद्ध कारवाई की मांग करती है जिससे कि माइको का वातावरण दोबारा सामान्य हो सके.

सीटू अपनी संबद्ध यूनियनों को कर्नाटक सरकार की इन क्रूर चालों की निंदा करने का आह्वान करती है. और साथ ही यह मांग करती है कि इस कदम को रद्द किया जाए.

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

दक्षिण अफ्रीका में खान मजदूरों का शोषण

कोयले की अंतर्राष्ट्रीय मंडी दिनों दिन मुनाफे की ओर जा रही है क्योंकि पश्चिमी देश आजकल कोयला जमा करने की भारी योजना तैयार करने में लगे हुए हैं. इस वर्ष जनवरी में दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गए अमरीका के कांग्रेसमैन जेम्स सानतिनी ने यह कहते हुए इस बात को साफ जाहिर किया कि—"हम यहां अफ्रीका विशेषतः दक्षिण अफ्रीका खनिज उद्योग की देन का जायजा लेने तथा इसका स्थायित्व निर्धारित करने आए हैं. दक्षिण अफ्रीका अमरीका की खनिज की पूर्ति का एक मुख्य स्रोत है." इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में कोयला उद्योग सोने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग बन गया है.

दो समस्याएं

कोयले को रिचर्डस बे टर्मिनल से पश्चिम ले जाने में मालिकों और सरकार को दो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. सबसे पहले नई खाने खोलने व अपने मुनाफे को लगातार बढ़ाते रहने के लिए उन्हें अधिक पूंजी विनियोग की आवश्यकता है. यह विनियोग दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक स्थायित्व पर निर्भर करता है. यह स्थायित्व तब तक असंभव है जब तक कि रंगभेद नीति समाप्त नहीं होगी. दूसरी बात यह है कि कोयले को पश्चिम ले जाने के लिए और अधिक कुशल कारीगरों की आवश्यकता है.

अश्वेत मजदूरों को कुशल कार्य में भेजने का भूतपूर्व प्रधान मंत्री वोस्टर, एक एम. डब्लू. यू. के नेता एरी पोलस तथा अन्य प्रतिक्रियावादी संगठन विरोध करते हैं.

कुशल श्रम की आवश्यकता

1978 तक 25% श्वेत कुशल श्रम शक्ति को खान उद्योग में लगाया गया था जो कि उस समय भी काफी नहीं थी. इससे पहले, कुशल मजदूरों का दक्षिण अफ्रीका आकर बस जाना ही कुशल मजदूर शक्ति का मुख्य स्रोत था. किन्तु पिछले कुछ सालों में देश में आने वाले लोगों की संख्या लगातार घट रही है. इस समस्या का समाधान करने के लिए अश्वेत मजदूरों को भर्ती किए जाने तथा उन्हें ऐसे कुशल कार्यों के लिए प्रशिक्षण दिए जाने के प्रयत्न किए गए हैं. किन्तु श्वेत खान के मजदूरों ने इसका जोरदार विरोध किया. पिछले साल छः से 13 मार्च तक ओकीफ खानों के श्वेत मजदूरों ने अश्वेत मजदूरों को कुशल पदों पर नियुक्त करने के विरोध में एक 'गैर कानूनी' हड़ताल की. वे यह भी मांग कर रहे थे कि इस उद्योग में श्वेत मजदूरों के लिए आरक्षण को समाप्त न किया जाए. (श्वेत होने के कारण उनपर कोई कानूनी कारवाई नहीं की गई.) इस हड़ताल का प्रभाव देशभर की लगभग 70 खानों पर पड़ा तथा राजनीतिक मुद्दे सामने आए. वीहान आयोग जब अपनी दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तो ये मुद्दे और स्पष्ट रूप से सामने आएंगे. वीहान आयोग की सिफारिशों में मिली-जुली यूनियनें बनाने और खान उद्योग की भविष्य में सही आधार पर संरचना करना शामिल है. इस रिपोर्ट की हाल ही में आ जाने की संभावना है.

खानों की हालात

अंतर्राष्ट्रीय मंडी में मूल्य वृद्धि से जो लाभ खान उद्योगों को होता है उसका कोई प्रभाव अश्वेत मजदूरों पर नहीं होता. उन्हें इस लाभ में से कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है. अश्वेत और श्वेत मजदूरों के वेतन में असमानता अभी भी मौजूद है. और जिन परिस्थितियों में अश्वेत मजदूर जी रहे हैं वे बहुत बुरी हैं. उनकी शिकायतें हैं—कम मजदूरी, जीवन यापन की कठिन परिस्थितियां, कम्पनियों का मजदूरों से जाति के आधार पर भेदभाव करने की नीति, भोजन का निम्न स्तर तथा यह तथ्य कि मजदूरों की पत्नियाँ व बच्चों को खानों के आस पास के क्षेत्रों में बसने की अनुमति न दी जाना.

अश्वेत मजदूर दिन में आठ घंटे भूमि की तह में काम करते हैं. सरकार द्वारा नियत काम के घंटों को व्यवहार में विशेषतः रात की पाली में बढ़ा दिया जाता है. अश्वेत मजदूरों को खान से बाहर तभी लाया जाता है जब सभी श्वेत मजदूर पहले ही बाहर आ चुके होते हैं. कभी-कभी लिफ्ट कर्मचारी लिफ्ट चलाने से इंकार कर देते हैं. ऐसे मौकों पर अश्वेत मजदूरों को भूमि के भीतर ही सोना पड़ता है.

खानों में दुर्घटनाएं

हर साल खान-दुर्घटनाओं में औसतन 100 मजदूर मृत्यु के शिकार और लगभग 28000 घायल होते हैं. बचाव की सुविधाएं बहुत कम हैं और वह भी विशेषतः खानों के निचले गहरे तहखानों में जहां खतरा होने के कारण केवल अश्वेत मजदूरों को भेजा जाता है और यही अश्वेत मजदूर मृत्यु के शिकार होते हैं. गहरी खानों से तात्पर्य है अधिक तापमान, गर्मी और अधिक चट्टान विस्फोट. उचित प्रशिक्षण व अनुभव की कमी, शटलकारों, मकेनिकल लोडरों और अन्य संयंत्रों के कारण दुर्घटनाएं अधिक होती हैं. काम करने की बुरी परिस्थितियों और खतरा होने के कारण अधिक गैर हाजरी और उत्साह की कमी हो जाती है जिसमें दुर्घटनाओं की ज्यादा संभावना होती है. 1978 में 65 कोयला खानों में 98 अश्वेत और सात श्वेत मजदूरों की मृत्यु हुई जबकि 1742 अश्वेत और 176 श्वेत मजदूर घायल हुए.

[शेष पृष्ठ चार पर]

दक्षिण अफ्रीका......

[पृष्ठ तीन का शेष]

मशीनीकरण

मालिकों के अनुसार खानों की समस्याओं का एकमात्र समाधान मशीनीकरण ही है. इससे मजदूरों की आवश्यकता कम हो जाएगी. साथ ही एंग्लो अमेरिकन के प्रबंध निर्देशक के अनुसार— "हमें इस बात को मानना चाहिए कि आने वाले सालों में गहरी खानों की कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए मजदूर मिलना और अधिक मुश्किल हो जाएगा" पश्चिम देशों से इस उच्चस्तरीय तकनीकी को लाने से अर्धकुशल मजदूरों व उच्चस्तरीय तकनीकी शिक्षा प्राप्त छोटे-छोटे गुटों की संख्या में वृद्धि करनी पड़ेगी. खान मजदूरों ने समय-समय पर अधिक मजदूरी और काम करने की अच्छी परिस्थितियों के लिए प्रदर्शन कर अपनी शक्ति जाहिर की है. सरकार और खान मालिक दोनों ही मजदूरों के इस संघर्ष को काबू में लाने के लिए नए-नए रास्ते और साधन तलाश रहे हैं.

बेरोजगारी

सरकार और मालिकों का तर्क है कि मशीनीकरण करना अच्छा है क्योंकि इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी. इस बात की पुष्टि के लिए वे उदाहरण देते हैं कि कोयला खान उद्योग में 1965 में 81000 मजदूर काम कर रहे थे जबकि 1976 में 83000 ने काम किया. 23% अथवा 20 लाख से अधिक बेरोजगारी के इस दौर में 11 सालों में 2000 नौकरियों की यह संख्या कोई मायने नहीं रखती.

दक्षिण अफ्रीका के कोयला उद्योग के प्रभाव से फ्रांस, ब्रिटेन और अमरीका की खानें बंद हो रही हैं और वहां के मजदूरों के रोजगार के अवसर समाप्त हो रहे हैं. यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का आह्वान करती है जो तभी अर्थपूर्ण होगी जब दक्षिण अफ्रीका के खान-मजदूर स्वयं को ट्रेड यूनियनों में एकताबद्ध कर पाएंगे. जबकि खान मालिक दिन प्रतिदिन अधिक लाभ कमा रहे हैं और निर्यात में वृद्धि हो रही है अफ्रीका के मजदूरों के हिस्से में कठोरता और शोषण ही है.

महाराष्ट्र व गुजरात के अध्यादेशों की सीटू द्वारा निंदा

सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के सेक्रेटरी एम. के. पंधे ने 16 मई को ह बयान जारी किया :

सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस उन दो अध्यादेशों की निंदा करती है जिन्हें राष्ट्रपति ने जारी करके महाराष्ट्र और गुजरात की सरकार को तथाकथित आवश्यक सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगाने का अधिकार दे दिया है. अध्यादेशों द्वारा पुलिस को किसी भी मजदूर को हड़ताल में भाग लेने और प्रोत्साहन देने के लिए बिना किसी वारंट गिरफ्तार करने, जेल भेजने और जुर्माना करने के मनमाने अधिकार दे दिए गए हैं.

अध्यादेशों में तालाबंदी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है. इस तरह से ये प्रबंधकों को काम रोकने की पूरी आजादी देते हैं तथा केंद्रीय सरकार की नीयत को साफ जाहिर करते हैं.

समूचे देश में एक पार्टी का शासन लागू करने के लिए इन्दिरा कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा अधिनायकवादी कदम उठा रही है तथा देश में मजदूर वर्ग आंदोलनों का दमन कर रही है. जब ये हमले चुनाव अभियान के दौरान ही किए जा रहे हैं तो कोई भी यह समझ सकता है कि चुनाव के बाद क्या होगा.

सीटू तमाम संबद्धताओं के मजदूरों व यूनियनों से यह अपील करती है कि वे इन घातक अध्यादेशों के खिलाफ आवाज उठाएं ताकि सरकार इन्हें तुरंत वापस लेने के लिए मजबूर हो.

सीटू सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से एकजुट होने की अपील करती है ताकि इन गैरजनवादी कदमों के खिलाफ एकजुट अभियान चलाया जा सके.

21 अप्रैल...

[पृष्ठ दो से आगे]

जिसमें प्रवक्ता ने अखिल भारतीय दिवस को विस्तार से समझाया.

निमच—अफीम और एल्कोलाइड मजदूर यूनियन ने फैक्टरी के द्वार पर एक सभा का आयोजन किया.

राजाहमुन्द्री—फोर्ट गेट पर एक आम सभा की गई. मजदूरों ने प्रदर्शन किया तथा बाद में सभा में हिस्सा लिया.

ऋषिकेश—केमिकल वर्कर्स यूनियन ने एक आम सभा का आयोजन किया.

हजारीबाग—एक जुलूस निकाला गया जो बाद में एस. के. चटर्जी की अध्यक्षता में हुई रैली में बदल गया. यह रैली कोलियरी मजदूर सभा आफ इंडिया की स्थानीय इकाई ने आयोजित की थी.

जयपुर—गेट सभाएं व स्थानीय सभाएं करके इस दिवस को मनाने की तैयारियां की गईं. जुलूस निकाले गए तथा जयपुर, कोटा, रावलभाटा, गंगा नगर, कृष्णगढ़, चित्तौड़, उदयपुर, बीकानेर तथा अन्य स्थानों में जिला व सब डिविजनल हैडक्वार्टर्स के सामने प्रदर्शन किए गए. मजदूर वर्ग ने इसमें अधिक सहयोग दिया. कुछ स्थानों पर अन्य संस्थाओं से संबद्ध मजदूरों ने भी प्रदर्शनों में भाग लिया.

सीटू का नया प्रकाशन

कोयला खदानों में मजदूरों के लिए कल्याण योजनाओं का

चेहरा बेनकाब

मूल्य : 40 पैसे

मिलने का पता :

सीटू कार्यालय
6, तालकटोरा रोड
नई दिल्ली-110001

समूचे देश में मई दिवस मनाया गया

सीटू अध्यक्ष, बी. टी. रणदिवे ने गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, में एक मई दिवस रैली को संबोधित करते हुए देश के मजदूर वर्ग का आह्वान किया कि वे हमारे देश के खिलाफ साम्राज्यवादी साजिशों, खासतौर से अमरीकी साजिशों, को करारी शिकस्त दें. उन्होंने मजदूरों को सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद का झंडा बुलंद करने को कहा. उन्होंने मजदूर वर्ग का आह्वान किया कि वह एकजुट हो और अधिनायकवादी ताकतों के हमलों के खिलाफ संघर्ष करें और उन्हें विधान सभा चुनावों में शिकस्त दें.

सीटू के उपाध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार के मुख्य मंत्री, ज्योति बसु ने कलकत्ता में मई दिवस रैली को संबोधित करते हुए एकता को स्थायी रखने की अपील की और कहा कि केवल यह एकता ही देश में फैली गैर-जनवादी और अधिनायकवादी ताकतों को शिकस्त दे सकेगी. तालाबंदी आदि पर बोलते हुए उन्होंने मजदूर वर्ग को चेतावनी दी कि उनका आखिरी और एकमात्र हथियार हड़ताल है जिसे ठीक समय पर ही इस्तेमाल करना चाहिए और प्रबंधकों के उकसाने पर कभी नहीं. रैली को सीटू, एटक, उटक, टी.यू.सी.सी., 12 जुलाई कमेटी, ईस्टर्न रेलवेमैन यूनियन, मर्केन्टाइल फेडरेशन आदि ने संयुक्त रूप से आयोजित की थी.

अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का दिन, मई दिवस समूचे देश में मनाया गया. रैलियां और जुलूस आयोजित किए गए. दिल्ली में दिल्ली सीटू, इटक और नार्थ जोन इंश्योरेंस एंप्लाईज एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से एक रैली आयोजित की जिसे अन्यों के अलावा मुहम्मद इस्माइल, एम. पी., और सुनिल मोइत्रा, एम. पी., ने संबोधित किया. फरीदाबाद में दीवान गांधी की अध्यक्षता में आयोजित रैली को सुशील भट्टाचार्य, एम.पी., ने संबोधित किया. एक विशाल रैली सोनीपत जिला सीटू ने आयोजित की.

सीटू, एटक और अन्य संगठनों ने इकट्ठे होकर देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश और अन्य स्थानों पर रैलियां कीं. सीटू की स्थानीय कमेटियों ने बेतिया बंसी, हिसार, राजामुंद्री, इंदोर, बुलंदशहर, शिकारपुर, सिकंदराबाद, पुरनापानी, पानीपत, जयपुर, मद्रास आदि में अनेक रैलियां आयोजित कीं. इन सभी सभाओं में राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पर कई प्रस्ताव अपनाए गए.

आसाम में वार्ता द्वारा समझौता करने का अनुरोध

सीटू की आसाम राज्य कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, अमल घोष दस्तीदार, ने 12 मई को यह ब्यान जारी किया :

आसाम में 'विदेशियों' के सवाल पर सात महीने से चले आ रहे आंदोलन ने राज्य की समूची अर्थ व्यवस्था को सर्वनाश के कगार पर ला कर खड़ा कर दिया है. काफी अर्से से रिफाइनरीज, फर्टीलाइजर, और सीमेंट फैक्ट्रियों में उत्पादन बंद हो गया है. टिंबर, जूट और बंबू के परिवहन पर रोक लगाने के कारण 20,000 प्लाईवूड मजदूर रोजगार-रहित हो रहे हैं तथा उनके परिवार के एक लाख के करीब सदस्य भुखमरी का सामना कर रहे हैं. यही हालत सैंकड़ो हैंडलूम मजदूरों और उनके परिवारों की है जिसमें सोआलकूची भी शामिल है. इनके अलावा. लाखों असंगठित मजदूर भी जो टिंबर, बंबू आदि के परिवहन व प्रोसेसिंग में विकास कार्य में लगे है, बरोजगार है और भूखमरी का सामना कर रहे हैं. अगर जल्दी ही हालत में सुधार नहीं हुआ तो दूसरे अनेक छोटे उद्योग भी बंद हो जाएंगे, और यहां तक कि चाय बगानों में बहुत बड़ी संख्या में ले आफ हो सकता है,

ग्रामीण गरीब तबका भी गहरे आर्थिक संकट का समना कर रहा है जो भारी संख्या में उपद्रवों और परिवहन में बार बार रूकावटों से पैदा हुआ है. जहां किसान औद्योगिक वस्तुओं के लिए बहुत ऊंचे दाम देता है वहां अपने उत्पाद के लिए जिसमें जूट और बंबू भी शामिल है, केवल मामूली दाम मिलते हैं.

इसलिए सीटू की आसाम राज्य कमेटी केंद्रीय सरकार का आसाम में संपूर्ण आर्थिक संकट की ओर ध्यान दिलाते हुए अनुरोध करती है कि यह बातचीत से समझौता करके मेहनतकश जनता को भुखमरी से और समूची अर्थव्यवस्था को सर्वनाश से बचाने के लिए तुरंत और उपयुक्त कदम उठाए.

राज्य कमेटी आसाम में मौजूदा आंदोलन के संचालकों से भी अनुरोध करती है कि वे आसाम की जनता की कठिनाइयों को महसूस करें और बातचीत द्वारा अपनी मांगों पर शांतिपूर्वक समझौता करने का रास्ता अपनाएं.

कामगार महिला मांग दिवस मनाया गया

कामगार महिलाओं की मांगों को प्रकाश में लाने के लिए आल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी आफ वर्किंग वूमैन्न ने हाल ही में 28 अप्रैल को अखिल भारतीय दिवस मनाने का आह्वान किया था, इस आह्वान पर पुरनापानी में करीब 1000 मजदूरों व कामगार महिलाओं ने एक सभा आयोजित की. सभा में बोलते हुए वक्ताओं ने कामगार महिलाओं का आह्वान किया कि वे एकजुट होकर अपने शोषण के खिलाफ और अपने जनवादी व ट्रेड यूनियन अधिकारों के लिए संघर्ष करें.

इसी प्रकार का एक रैली नेल्लौर में स्पिनिंग मिल के गेट पर आयोजित की गई. इस दिन पोस्टर आदि लगाए गए और मजदूरों ने बिल्ले लगाए रैली को कई साथियों ने संबोधित किया.

भारत में लगातार बढ़ते औद्योगिक विवाद

औद्योगिक विवादों के कारण 1979 में कुल मिलाकर 3 करोड़ 70 लाख मनुष्य-दिन (मैनडेज) बेकार हो गए. इन विवादों में मजदूरों द्वारा की गई हड़तालें और प्रबंधकों द्वारा की गई तालाबंदियां शामिल हैं. यह संख्या 1978 और 1977 की तुलना में कहीं ज्यादा है. 1978 में 2 करोड़ 80 लाख मनुष्य दिन बेकार गए थे जबकि 1977 में यह संख्या 2 करोड़ 50 लाख थी. आसमान छूते दामों, मुद्रास्फीति की ऊंची दर विक्टिमाइजेशन में वृद्धि, छंटनी, स्वचालन, बढ़ती बेरोजगारी आदि के कारण मजदूरों ने प्रबंधकों से बातचीत द्वारा नए समझौते करने की मांग की ताकि उनके कार्य व निर्वाह की हालतों में सुधार हो सके. लेकिन प्रबंधकों के अड़ियल रवैये और उनकी व सरकार की मजदूर वर्ग विरोधी नीतियों के कारण मजदूरों के सभी प्रयास बेकार हो गए और उनके पास हड़ताल के अलावा और कोई रास्ता नहीं था.

बेकार गए मनुष्य-दिनों की संख्या में वृद्धि हड़तालों और तालाबंदियों की लहर को दर्शाती है. साथ ही यह मजदूर वर्ग के अपने आर्थिक सुविधाओं और ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकारों के लिए तथा प्रशासन व पुलिस की मदद से मालिकान के बढ़ते हमलों के खिलाफ लड़ाई करने के पक्के इरादे का सूचक है. मजदूर वर्ग की एकता और उनके संघर्ष को नाकामयाब करने के लिए मालिकान आमतौर पर छंटनी, क्लोजर और तालाबंदियां कर देते हैं, तथा मजदूरों को विक्टिमाइज करते हैं. लेकिन मजदूर वर्ग ने एकजुट कार्यवाहियों आदि से अधिक सूझ-बूझ का इजहार किया है. मजदूर वर्ग के एक हिस्से ने दूसरे हिस्से के संघर्षों के साथ एकजुटता कार्यवाहियां आयोजित की. ऐसे घेराव और हड़तालों की संख्या 1977 में क्रमशः 110 और 127 थी जो बढ़कर 1978 में क्रमशः 138 और 135 हो गई.

इंडियन लेबर जरनल ने अपने अप्रैल 1980 के अंक में 1977 और 1978 के लिए भारत में औद्योगिक विवादों की समीक्षा प्रकाशित की है. इस समीक्षा के आधार पर कारण के अनुसार औद्योगिक विवादों का वर्गीकरण सारिणी-1 में किया गया है. औद्योगिक विवाद से मतलब है कि सभी कर्मचारियों या उनके एक ग्रुप द्वारा अपनी शिकायत प्रकट करने के लिए काम रोक देना और मालिकान द्वारा सभी कर्मचारियों को या उनके एक ग्रुप को अस्थाई तौर पर काम न देना.

इस सारिणी से पता चलता है कि आमतौर पर औद्योगिक विवादों की कुल संख्या बढ़ी है और खासतौर से विक्टिमाइजेशन के खिलाफ विवादों की संख्या में वृद्धि हुई है.

तालाबंदियों के कारण प्रति विवाद [शेष पृष्ठ पंद्रह पर]

सारिणी--II

विषय	1977	1978
क. निम्न के कारण कुल समय की हानि		
(1) हड़तालों से	13,410,141	15,423,344
(2) तालाबंदियों से	11,909,931	12,916,855
(3) हड़तालों और तालाबंदियों से	25,320,072	28,340,199
ख. समय की हानि प्रति		
(1) हड़ताल	4,983	5,584
(2) तालाबंदी	27,958	30,393

सारिणी-I

	1977				1978			
	विवादों की संख्या		बेकार हुए मनुष्य दिनो की संख्या		विवादो की सख्या		बेकार हुए मनुष्य दिनों की संख्या	
कारण-ग्रुप	संख्या	कुल का प्रतिशत	संख्या	कुल का प्रतिशत	सख्या	कुल का प्रतिशत	संख्या	कुल का प्रतिशत
वेतन और भत्ते	925	31.2	8,738,672	34,9	887	28.7	7,500,294	26.8
बोनस	450	15.2	4,624,065	18.5	308	9.9	2,832,149	10.1
कार्मिक	599	20.2	2,337,591	9.3	675	21.8	3,174,097	11.3
छटनी	82	2,8	211,452	0.9	75	2.4	208,584	0.8
छुट्टी व कार्य के घंटे	66	2.2	269,816	1.1	62	2.0	121,473	0.4
विक्टिमाइजेशन	261	8.8	5,830,557	23.3	330	10.7	10,361,845	37.0
अन्य	581	19.6	5,005,205	12.0	757	24.5	3,800,973	13.6
अवर्गीकृत	153	—	302,714	—	93	—	340,784	—
कुल जोड़	3,117	100.0	25,320,072	100.0	3,187	100.0	28,340,190	100.0

नोट : प्रतिशत केवल वर्गीकृत कारणों के लिए निकाली गई है.

सारिणी—III—1977 और 1978 में औद्योगिक विवाद (राज्यों के अनुसार)

राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र	1977			1978		
	विवादों की संख्या	प्रभावित मजदूरों की संख्या	बेकार गए मनुष्य-दिनों की संख्या	विवादों की संख्या	प्रभावित मजदूरों की संख्या	बेकार गए मनुष्य-दिनों की संख्या
आंध्र प्रदेश	116	74,304	694,067	206	115,285	816,601
आसाम	8	10,008	10,739	18	18,940	55,937
बिहार	264	197,357	1,706,147	306	148,624	1,045,104
गुजरात	165	45,639	302,660	181	68,270	445,184
हरियाणा	99	37,565	583,722	107	22,781	620,130
हिमाचल प्रदेश	4	1,558	3,724	11	1,499	8,622
जम्मू व कश्मीर	3	2,041	7 150	4	586	4,913
कर्नाटक	90	59,489	721,768	92	70,093	575,657
केरल	184	156,267	2,110,823	146	84,492	2,055,114
मध्य प्रदेश	168	144,550	1,068,597	199	112,249	485,333
महाराष्ट्र	553	500,069	3,093,225	318	288,501	3,716,319
मनीपुर	1	125	1,175	*	290	580
मेघालय	—	—	—	*	428	856
नागालैंड	—	—	—	*	287	574
उड़ीसा	85	49,047	224,039	47	22,522	176,318
पंजाब	65	45,118	294,471	106	35,170	217,318
राजस्थान	165	72,692	1,006,076	144	44,948	569,512
सिक्किम	—	—	—	1	323	158
तमिलनाडु	316	286,487	2,910,513	394	216,129	2,365,417
त्रिपुरा	3	209	2,429	8	7,314	1,006
उत्तर प्रदेश	195	107,643	1,602,821	247	161,862	2,717,085
पश्चिम बंगाल	480	307,344	8,488,654	548	416,804	12,004,897
अंडमान निकोबार	16	4,126	10,622	6	2,068	2,449
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	*	209	418
चंडीगढ़	7	2,191	21,731	6	1,408	2,877
दादरा व नगर हवेली	2	288	2,360	1	100	2,200
दिल्ली	52	29,484	101 506	46	32,231	332,756
गोवा, दमन व दीव	47	15,729	92,078	25	10,041	138,848
लक्षद्वीप	2	73	1,618	—	—	—
मिजोराम	—	—	—	*	158	316
पांडिचेरी	27	43,812	257,357	19	32,021	135,824
कुल जोड़	3,117	2,193,215	25,320,072	3,187	1,915,603	28,340,199

* अखिल भारतीय हड़तालों की संख्या 1977 और 1978 में क्रमश: 8 और 2 थी. इनको उन राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में शामिल कर लिया गया है जिनमें सबसे ज्यादा मनुष्य-दिनों की हानि हुई. लेकिन इन हड़तालों से प्रभावित मजदूरों की संख्या और मनुष्य-दिनों की हानि संख्या संबंधित राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र में दी गई हैं.

बहुराष्ट्रीय कंपनियों और हथियारबंदी के खिलाफ संघर्ष

विकास पर विश्व ट्रेड यूनियन सम्मेलन

बेलग्राद में 22 से 25 अप्रैल तक एकत्रित 85 देशों की ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने विकासशील देशों पर हो रहे नव उपनिवेशवादी देशों विशेषतः बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और हथियारबंदी के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद की. साथ ही उन्होंने सभी विकसित देशों को विकासशील देशों की सहायता करने का आह्वान किया. शांति और विकास के लिए हुए इस विश्व सम्मेलन ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों, हथियारों, नस्लवादियों और जातिवादी प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष को और अधिक दृढ़ बनाया है.

कनफेडरेशन आफ काउंसिल आफ ट्रेड यूनियंस आफ युगोस्लाविया (सी. यू. टी. वाई.) द्वारा आयोजित विकास पर हुई इस विश्व ट्रेड यूनियन सम्मेलन को फ्रांस, इटली और अलजीरिया की ट्रेड यूनियनों ने काफी आर्थिक सहायता दी. इस सम्मेलन में 85 देशों के 122 प्रतिनिधियों के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र, यूनिडो, एफ. ए. ओ., यूनेस्को, आई. एल. ओ., डब्लू. एफ. टी. यू., आई. सी. एफ. टी. यू. और डब्लू. सी. एल. के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया. ब्रिटेन पश्चिम जर्मनी और अमरीका की ओर से कोई प्रतिनिधि वहां उपस्थित न था. भारत की ओर से सीटू, एटक, एच. एम. एस. और इंटक के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया. सीटू का प्रतिनिधित्व सीटू के सचिव नृसिंह चक्रवर्ती ने किया.

एक जुटता के लिए पहलकदमी

पूंजीवादी दुनिया में मौजूदा आर्थिक स्थिति एक गहरी समस्या बन गई है. इसमें कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों पर अपना प्रभाव डालती हैं. ये विशेषताएं हैं—बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास की धीमीगति, हथियार, उद्योग व बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, धन का केन्द्रीकरण, जनसंख्या में बढ़ोत्तरी और सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं में कटौती. सारी दुनिया में विशेषत: विकासशील देशों में इस संकट का सारा भार मजदूर वर्ग के कंधों पर आ पड़ा है. विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति तेजी से बिगड़ रही है. बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इन देशों का सारा धन लूटकर ले जा रही हैं और इस प्रकार उनके नव उपनिवेशवादी पंजे और अधिक मजबूत बनते जा रहे हैं. हथियारों की दौड़ से विश्व शांति और विकासशील देशों की स्वतंत्रता को भारी खतरा है. बहुत से देशों में जाति के आधार पर भेदभाव और रंगभेद नीति के हाथों लोगों का अधिक से अधिक शोषण किया जा रहा है. और उनके जनवादी आंदोलनों को बुरी तरह कुचला जा रहा है. इन हालात में इस सम्मेलन को आयोजित किया गया जिसे कि सम्मेलन में भाषण देते हुए प्लेनरी सेशन के अध्यक्ष यूगोस्लाविया के माइका स्पाइलजेक ने "आपसी सहानुभूति और सहयोग की ट्रेड यूनियन सभा" कहा.

हथियारबंदी के खिलाफ

सम्मेलन की शुरूआत 22 अप्रैल को यूगोस्लाविया के जोसिप फ्रेनिक ने की और सभी प्रतिनिधिओं ने बारी-बारी से सत्र की अध्यक्षता की. हर सत्र के लिए 20 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल बनाए गए थे. सम्मेलन में प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए यूगोस्लाविया की फेडरल काउंसिल के अध्यक्ष जुरानोविच ने कहा कि हथियारों पर किया गया खर्च 1977 में 300 बिलियन डालर के मुकाबले 1980 में 450 बिलियन डालर हो गया है. (देखिए आरमामेन्ट पर लेख, सीटू मजदूर, मार्च 1980). उन्होंने ट्रेड यूनियन आंदोलन से हथियारों की इस बढ़ौतरी के खिलाफ लड़ने की अपील की जिससे कि इन पर खर्च हो रहा बेहिसाब धन विकास के कामों में लगाया जा सके.

शोषण और दमन

प्रतिनिधियों ने अपने भाषण में न सिर्फ अपने देश के तथ्यों की जानकारी दी बल्कि विश्व-अर्थव्यवस्था पर भी प्रकाश डाला. कुछ वक्ताओं ने उन परिस्थितियों का भी जिक्र किया जिनमें विकासशील देशों के लोगों को शोषण तथा जोरदार दमन का शिकार बनना पड़ता है.

माइका स्पाइलजेक ने यह बताया कि दुनिया की जनसंख्या का तीसरा हिस्सा विश्व अर्थव्यवस्था के सिर्फ 3% पर जीवन बसर कर रहा है. यही कारण है कि विश्व में 20 करोड़ बच्चे भुखमरी से पीड़ित हैं. और विकासशील देशों में मनुष्य की जिंदगी औसतन 20 साल ही है.

बंगला देश की जातीय श्रमिक लीग के हबीब-उर-रहमान ने बताया कि मुजीब-उर-रहमान की हत्या के बाद लगभग 50,000 मजदूरों को नौकरियों से निकाल कर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र के तहत कर दिया गया. ट्रेड यूनियन कानूनों को इस प्रकार से संशोधित किया गया है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति ट्रेड यूनियन का कोई पद नहीं ले सकता है. इस कानून का फायदा उठाते हुए सरकार और प्रबंधक उन यूनियनों के कार्यकर्त्ताओं को जो उनके बताए रास्ते पर नहीं चलते तंग करते हैं. उन्होंने विश्व ट्रेड यूनियन आंदोलन से सहानुभूतिपूर्ण सहयोग की अपील की.

ब्राजील के प्रतिनिधि ने 1978 से अंतर्राष्ट्रीय एकता के लिए हो रही हड़ताल को समझाया. नामीबिया के प्रतिनिधि ने बताया कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जाति के आधार पर वेतन निर्धारण करती हैं. जिस काम के लिए श्वेत 3,400 डालर लेते हैं उसी काम के लिए अफ्रीका के अश्वेतों को 230 डालर दिए जाते हैं. उन्होंने नस्लवाद और रंगभेद नीति का जोरदार शब्दों में बिरोध करते हुए इसके विरुद्ध संघर्ष करने का आह्वान किया.

पूंजीवादी दुनियां में संकट

संघर्ष की यही मांग साउथ अफ्रीका कांग्रेस आफ ट्रेड यूनियंस के प्रतिनिधि [illegible]वीन बर्ग ने की जिन्होंने अपने देश के लोगों के कार्य और जीवन निर्वाह के हालात का विस्तार से बयान किया. उनके देश में ब्रिटिश उपनिवेशवादी राज कर रहे हैं. इससे पहले दक्षिण अफ्रीका तीन सौ सालों तक पुर्तगाली उपनिवेश था. जैसे-जैसे अफ्रीका के लोग अपने पडोसी राज्यों से सहायता लेकर संघर्षरत हो रहे हैं वैसे ही नस्लवादी शासकों को फ्रांस, ब्रिटेन और इस्राइली सरकारें न्यूकलियर हथियारों से लैस करने में सहायता दे रही है. उन्होंने रंगभेद के खिलाफ अदिस अबाबा में हुए घोषणा पत्र को लागू कराने के लिए विश्व स्तर पर एकजुटता का आह्वान किया.

ओ. ई. सी. डी के हाल के अधिवेशन जिसमें 24 विकसित पूंजीवादी देशों ने भाग लिया इस बात पर अपनी चिन्ता प्रकट की कि बेरोजगारी का प्रभाव एक करोड़ 80 लाख था. जो श्रम शक्ति के 5.25% भाग पर पड़ा. बढ़ रही मुद्रास्फीति और आर्थिक संकट के कारण अधिक से अधिक महिलाएं मजदूरी के लिए तैयार हो रही हैं. बेरोजगारी के रजिस्टर में महिलाओं की संख्या फ्रांस में 53%, बेलजियम में 50% और यूरोपीय आर्थिक साझा देशों (ई. ई. सी.) में कुल मिलाकर 50% है. यूरोपीय देशों में मुद्रास्फीति 15 से 19% और विकासशील देशों में 20 से 30% के बीच तक बढ़ गई है. और आर्थिक विकास की दर भी इसके साथ साथ कम हो रही है. भारत में बेरोजगारी एक करोड़ 80 लाख के आंकड़े दर्शाती है जबकि मुद्रास्फीति 20% तक पहुंच चुकी है.

पूंजीवादी देशों के इन बुरे हालात को पेश करते हुए सीटू के सचिव नृसिंह चक्रवर्ती ने सम्मेलन में यह बताया कि "सभी विकसित पूंजीवादी देशों में विकास दर 4% से 6% तक घट गई है और यह आंकड़े तेजी से शून्य दर की ओर जा रहे हैं. यू. एन. सी. टी. ए. डी. के हाल ही के अध्ययन के अनुसार दुनिया के सबसे गरीब 30 देशों का आर्थिक विकास 1980 में केवल 2.6% बढ़ेगा. भारत में इस विकास का अनुमान 1979-80 में 1% लगाया गया है.

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लूट

गैर ओपेक विकासशील देशों के बकाया कर्जों की चर्चा करते हुए जो कि 1973 में 77,000 अरब डालर के मुकाबले 1979 में 2,50,000 अरब डालर हो गया है और साथ ही इन देशों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा 1965 से 1970 तक किए गए धन के लूट की विस्तार से सूचना देते हुए सीटू सचिव ने सम्मेलन में कहा कि "रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने 1964-65 से 1969-70 के लगभग छः सालों तक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की सहयोगी 877 कम्पनियों के सर्वेक्षण के बाद यह निष्कर्ष दिया कि इस समय के दौरान 10,929 करोड़ रुपये देश से बाहर गए हैं.

तकनीकी ज्ञान के लिए

तकनीकी ज्ञान के आदान-प्रदान से मतलब है साम्राज्यवादी शरण में जाना. इस तकनीकी परिवर्तन में लगाए जाने वाले भारी व्यय को विकासशील देश सहन नहीं कर पाते हैं. यह व्यय एक साल में लगभग 600 करोड़ से 1200 करोड़ तक हो सकता है. ऊर्जा संकट के सारी दुनिया को प्रभावित करने के कारण विकसित देश ऊर्जा के लिए न्यूकलिया ज्ञान को देने से इन्कार कर देते हैं. सम्मेलन में यह सब विस्तार से बताते हुए सीटू सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि "कभी-कभी ये विकसित देशों से बेकार और वातावरण दूषित करनेवाली फैक्टरियां हटाकर विकासशील देशों में लगा देते हैं ताकि वहां की सस्ती मजदूरी का इस्तेमाल किया जा सके और इस प्रकार विकसित देश में भी संकट पैदा कर देते हैं".

विकासशील देशों को व्यापार में भी परेशानियां उठानी पड़ती हैं. अफ्रीका, कैरिबियन और पैसिफिक राज्यों (ए. सी. जी) के मंत्रियों की काउंसिल ने इस तथ्य पर चिन्ता व्यक्त की कि उनका व्यापार ई. ई. सी. देशों के साथ लोमे कन्वेंशन पर हस्ताक्षर होने के बाद व्यापार कम होकर मुनाफे से घाटे की ओर जा रहा है. इस तथ्य की ओर संकेत करते हुए तथा अंकटाड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए नृसिंह चक्रवर्ती ने कहा कि "विकासशील देशों को विकसित देशों के साथ व्यापार करने में 1700 अरब डालर का घाटा सहना पड़ेगा. इसका कारण जेनर लाइजर स्कीम आफ प्रफरेंसिज के तहत मिल रही छूट में कटौती होनी है. यह नाम मात्र की छूट असल में कुछ विकसित देशों का गठजोड़ है. भारत का जनवरी 1980 तक के दस महीनों का व्यापार का घाटा 1600 करोड़ रुपये के रिकार्ड को पार कर चुका है और साल के अंत तक यह घाटा 2000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो सकता है". ऐसे हालात में भी हथियारों पर भारी खर्च किया जा रहा है. फाइडेल केस्ट्रो के अनुसार एक साल में हथियारों पर 3,00,000 अरब डालर से अधिक खर्च किया जा रहा है. यदि इसे उत्पादन प्रक्रिया की ओर लगाया जाए तो साल भर में ही ऐच्छिक परिवर्तन लाया जा सकता है.

जबरदस्त गरीबी

बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उत्पादन स्तर हर साल 7500 करोड़ डालर बढ़ जाता है जोकि अमरीका को छोड़कर अन्य किसी भी देश के कुल उत्पादन से अधिक है. सीटू सचिव ने सम्मेलन में यह सूचना दी कि भारत में 4 सबसे बड़े 20 एकाधिकारी घरानों ने 1972 से 1978 के बीच अपनी सम्पत्ति लगभग

[शेष पृष्ठ दस पर]

हरियाणा

मिल्टन साइकिल मजदूरों की मांग

मिल्टन साइकिल इंडस्ट्रीज, सोनीपत, के मजदूर मिल्टन साइकिल मजदूर संघर्ष समिति (सीटू) के नेतृत्व में अपनी मांगों के लिए एक लंबे अरसे से संघर्षरत हैं. इसकी कई रिपोर्ट इस पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी हैं.

सबसे पहले 24 जुलाई 1978 को मजदूरों ने एक मांगपत्र प्रबंधकों को दिया था जिसमें एक जाली समझौते को चेतावनी भी दी थी. लेकिन प्रबंधकों द्वारा इस मांगपत्र पर विचार न करने के कारण इसने अब औद्योगिक विवाद का रूप ले लिया है और औद्योगिक न्यायालय में पड़ा है.

मांग पत्र दाखिल करने के तुरंत बाद से ही मजदूरों पर जुल्म ढाया जाने लगा. पुलिस के साथ साजिश करके कई मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया. अनेकों को झूठे मामलों में फसाकर आतंकित किया गया. उनके साथ बुरी तरह से मार पीट की गई. फिर मजदूरों को भूख हड़ताल करनी पड़ी लेकिन 10 दिसबर 1979 को हड़तालियों के टेंट आदि को उखाड़ दिया गया और उन्हें गिरफ्तार करके झूठे मामलों में फसा दिया गया.

घरेलू जांच के दौरान प्रबंधक मजदूरों को बुरी तरह से तंग कर रहें हैं, और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है. पिछले छः महीनों से फैक्ट्री के चारों ओर दफा 144 लगी है अनेक मजदूरों को मुअत्तिल कर दिया गया है और उनको या तो निलबंन भत्ता दिया नहीं जा रहा है या फिर उसमें कटौती की गई है.

सीटू समर्थक मजदूर आतंक के खास निशाने बनाए गए हैं. उनपर गुंडों द्वारा बार बार हमले कराए जा रहे हैं. ऐसे हालात में मजदूर संघर्ष समिति (सीटू) ने मांग की है कि धारा 144 तुरंत हटाई जाए, घरेलू जांच में श्रमिकों को न्याय दिया जाए, दमनकारी नीतियां खत्म की जाएं. मांग पत्र पर कोई समझौता किया जाए तथा निलंबित मजदूरों को सवेतन काम पर वापस लिया जाए.

रोहतक में तालाबंदियों में वृद्धि

रोहतक में तालाबंदियों, छंटनी और क्लोजर को कड़ी लगातार बढ़ रही है और ऐसा लगता है कि इस इलाके के उद्योगपति थे हथियार बार-बार अपनाकर मजदूरों के संघर्ष का दमन करना चाहते हैं. नवभारत इंडस्ट्री और ए.के. आटोमोबाइल्स में बिना किसी बुनियाद के तालाबंदी कर दी गई है. सुदेरटीन और सिनिदी आटोवर्क्स के मजदूरों को तंग करने के लिए बंद कर दिया गया है.

स्थानीय पुलिस की सहायता से प्रबंधक मजदूरों के खिलाफ झूठे मामले बनाकर तंग कर रही है. सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है और मजदूरों की समस्याओं पर कहीं कोई विचार नहीं किया जा रहा है. सीटू की जिला कमेटी ने मजदूरों के संघर्ष का समर्थन किया हैं और राज्य सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है ताकि इस क्षेत्र में औद्योगिक शांति बने तथा फैक्टरियां खोली जाएं.

विश्व ट्रेड यूनियन सम्मेलन

[पृष्ठ नौ से आगे]

90% बढ़ा ली है. दूसरी ओर यूनिडो सम्मेलन के पर्चे में इस ओर संकेत किया गया है कि देश के 80 करोड़ लोग गरीबी और भुखमरी से पीड़ित हैं. जहां तक भारत का संबंध है यहां की 70% जनसंख्या गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जी रही है".

1974 की तीन सप्ताह लंबी जोरदार रेलवे हड़ताल के तथा 1975-77 के आपातकाल में सारे देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन के अत्याचारी दमन का हवाला देते हुए नृसिंह चक्रवर्ती ने कहा कि "विश्व के ट्रेड यूनियन आंदोलन का यह कर्त्तव्य है कि विकासशील देशों में हो रहे मजदूर वर्ग के संघर्ष का समर्थन करे".

एकजुट संघर्ष का आह्वान

सीटू सचिव नृसिंह चक्रवर्ती ने सम्मेलन का आह्वान किया कि "सभी देशों के मजदूर वर्ग को जो निजी पूंजी के शोषण का शिकार है एक मंच पर आकर हथियारों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ तथा सभी देशों के सही विकास के समर्थन में लड़ाई लड़नी चाहिए. उन्हें उन सभी बनावटी मुश्किलातों से उबरना चाहिए जिन्हें शोषक वर्गों ने जान बूझ कर उनके रास्ते की बाधा बनाया है. क्योंकि समाजवाद की स्थापना किए बिना इन मुश्किलातों को सुलझाने का कोई स्थायी हल पेश नहीं किया जा सकता फिर भी मजदूर को चाहिए कि एकताबद्ध होकर हथियारों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरुद्ध तथा शांति बनाए रखने और न्यूकलियर हथियारों पर पाबंदी लगाने के लिए संघर्ष करें".

सत्र में सभी कमेटियों ने ज्ञापन के खाके पर तथा भिन्न-भिन्न प्रतिनिधियों द्वारा सुझाए गए संशोधन प्रस्तावों पर चर्चा की. सीटू ने 20 संशोधन पेश किए. खाके की यह विशेषता थी कि इसमें समाजवादी देशों और पूंजीवादी देशों के साथ समानता बरती गई थी. सीटू ने संशोधन के जरिए इन दोनों पद्धतियों में फर्क किया और ज्ञापन को और मजबूत बनाया. चीन के प्रतिनिधि मंडल ने अपने विचार जाहिर करते हुए कहा कि एक देश द्वारा दूसरे देश में मिलिटरी दखलअंदाजी और आक्रामकता ने विश्व में एक समस्या बना रखी है और जब तक इस समस्या को सही तरह से काबू में नहीं किया जाएगा विकास के प्रश्न पर कोई काम नहीं किया जा सकता. सभी संशोधन प्रस्तावों पर चर्चा कर चुकने के बाद अंतिम रूप में ज्ञापन तैयार किया गया जो सर्व सम्मति से मंजूर कर लिया गया. इस 'ज्ञापन' को इस साल के अंत में संयुक्त राष्ट्र की जनरल एसेम्बली सत्र में पेश किया जायगा.

दि वर्किंग क्लास

सी आई टी यू का अंग्रेजी मासिक

एक प्रति की कीमत 50 पैसे

वार्षिक चंदा छः रुपये

मिलने का पता :

सीटू कार्यालय

6, तालकटोरा रोड

नई दिल्ली-110001

पटाखों की फैक्ट्री में विस्फोट से 50 से अधिक मजदूर मरे

मध्यप्रदेश में रायपुर से लगभग 17 किलोमीटर दूर मंदिर हसोड़ में स्थित पटाखों की कम्पनी 'तपाड़िया फायर वर्क्स' में एक विध्वंसक विस्फोट ने उस समय फैक्टरी में काम कर रहे लगभग सभी मजदूरों की जाने लीं. ये मजदूर उस फैक्टरी में भिन्न-भिन्न कार्य करके अपनी जीविका कमा पाते थे. अभी तक इस विस्फोट का कारण नहीं जाना जा सका है क्योंकि उस समय काम कर रहे व्यक्तियों में से कोई भी जीवित नहीं बचा.

वहां के निवासियों का कहना है कि 3 मई को सुबह लगभग 11 वजे उन्होंने एक धमाका सुना और वे लोग फैक्टरी की ओर भागे. किन्तु तब तक वहां कुछ भी शेष न बचा था. सारी फैक्टरी कुछ ही मिनटों में नष्ट हो गई तथा मजदूर लोग अन्दर ही जलकर मर गए. घंटों तक धुंआ छाया रहा जिससे घटनास्थल पर न पहुंचा जा सका. मनुष्यों के शरीरों के टुकड़े इधर-उधर बिखरे पड़े थे. पास ही स्थित एफ. सी. आई. के गोदाम के मजदूरों ने जैसे-तैसे सात बुरी तरह जले मजदूरों को बचा लिया किन्तु जो मजदूर अंदर थे वे सभी इस आग के शिकार हो गए. दमकल विभाग भी सक्रिय हो उठा किन्तु लोगों को बचाने का इंतजाम काफी नहीं था. डाक्टरों का भी इंतजाम नहीं था. पास के स्थानों के मजदूरों ने बचाव अभियान में आधी रात तक सहयोग दिया.

बाद की जांच से पता चला कि फैक्टरी में 200 से अधिक मजदूर काम करते थे. कुछ ठेके पर लाए जाते थे जिनमें महिलाएं और बच्चे अधिक थे. यह नहीं पता चल सका है कि विस्फोट के समय फैक्टरी में कितने मजदूर थे. मालिक का कहना है कि उसकी फैक्टरी में उस समय कोई बच्चा नहीं था और मजदूरों की संख्या सिर्फ 25-30 थी. किंतु पुलिस की रिपोर्ट से यह साबित होता है कि उन जले शवों में कुछ बच्चे भी थे और मृतकों की संख्या 35 पाई गयी. किंतु ऐसा कहा जाता है कि विस्फोट के समय वहां 50 से भी अधिक मजदूर काम कर रहे थे.

इनमें से अधिकतर मजदूर पास के लगभग 8 किमी. दूर माना शरणार्थी

[शेष पृष्ठ बारह पर]

अकेले फैक्ट्रियों में 1977 में तीन लाख से अधिक मजदूर घायल

हमारे अपने अनुभवों और रिपोर्टों से पता चलता है कि मिलों में दुर्घटनाओं की तादात लगातार बढ़ रही है तथा बहुत बड़ी संख्या में मजदूर इसके शिकार होते जा रहे हैं जिनमें से कई तो अपनी जान भी गंवा बैठते हैं. मालिक मजदूरों की रक्षा की परवाह किए बिना सिर्फ अपने लाभ से काम रखते हैं जिसके परिणाम स्वरूप मजदूरों की मृत्यु-संख्या लगातार बढ़ रही है. नीचे हम विभिन्न राज्यों में 1977 में जख्मी हुए मजदूरों की संख्या प्रकाशित कर रहे हैं. इन आंकड़ों को किसी व्याख्या की जरूरत नहीं है. ध्यान दिया जाए कि इन आंकड़ों में गोदी व बंदरगाह, रेलवे, यातायात, विमानसेवा तथा फैक्टरियों से भिन्न व्यवसायों में जख्मी हुए मजदूरों को नहीं गिना गया है. यदि हम इन आंकड़ों को भी सम्मिलित करें तो जख्मियों की संख्या एक भयावह शक्ल अख्तियार कर लेगी.

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	जानलेवा	घातक	कुल
आंध्र प्रदेश	53	6,838	6,891
असम	7	1,042	1,049
बिहार	45	7,517	7,562
गुजरात	75	31,495	31,570
हरियाणा	16	3,764	3,780
जम्मू और काश्मीर	—	50	50
कर्नाटक	44	14,337	14,381
केरल	17	6,003	6,020
मध्य प्रदेश	61	30,281	30,342
महाराष्ट्र	123	77,339	77,462
मेघालय	—	1	1
उड़ीसा	16	2,538	2,554
पंजाब	15	3,193	3,208
राजस्थान	21	5,258	5,279
तमिलनाडु	31	28,419	28,450
त्रिपुरा	—	28	28
उत्तर प्रदेश	88	13,983	14,071
पश्चिम बंगाल	68	78,539	78,607
अंडमान और निकोबार	—	130	130
चंडीगढ़	—	107	107
दिल्ली	4	2,832	2,836
गोआ, दमन और दिव	—	281	281
पांडिचेरी	2	1,598	1,600
कुल	686	3,15,573	3,16,259

स्रोत : इंडियन लेबर जनरल, अप्रैल 1980

प्रबंधकों की लापरवाही से दो मजदूर मरे

दो मजदूर मुहम्मद मुस्लिम और बलदेव जहरीली गैसों से भरे टैंक में जाते हीअपनी जान से हाथ धो बैठे. एक और मजदूर, जो अभी टैंक में घुस ही रहा था, बेहोश हो गया लेकिन दूसरे मजदूरों द्वारा खींच लेने से बचा लिया गया. इन मजदूरों को माउंट पैकर्ज, ओखला, नई दिल्ली के प्रबंधकों ने 12 मई को सफाई के लिए टैंक के अंदर जाने के लिए मजबूर किया था. प्रबंधकों ने न तो पहले कोई निरीक्षण ही किया और न ही उन्हें सुरक्षा के उपकरण दिए.

स्थानीय पुलिस अधिकारियों की मदद से प्रबंधक मामले को रफा-दफा करने की कोशिश कर रही हैं. पता चला हैं कि इस फैक्ट्री में 32 मजदूर काम करते हैं और प्रबंधकों ने कोई भी उपयुक्त रजिस्टर नही बना रखा है. दुर्घटना के बाद, प्रबंधकों ने सभी अपराधात्मक रिकार्ड नष्ट कर दिए हैं. मैनेजर और मालिक को साफ बरी जाने दिया जा रहा है.

सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी ने 14 मई को एक बयान में पुलिस की सांठगांठ और कोई कार्यवाही न करने की निंदा की है, और मांग की है कि प्रबंधकों को गिरफ्तार किया जाए तथा मृत मजदूरों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए. सुशील भट्टाचार्य, एम. पी., ने चेतावनी दी है कि यदि तुरंत कोई कार्यवाही नही की गई तो सीटू केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की मदद से प्रतिरोध कार्यवाही के लिए मजबूर होगी.

मालिक नए मजदूरों को कम वेतन पर बिना नाम दर्ज किए नौकरी देते हैं और अधिक से अधिक पैसा बनाने के लिए वह मजदूरों से हर प्रकार काम लेते हैं, चाहे उन्हें वह काम आता हो या नही. अत: मालिकों और प्रबधकों की नजर में मजदूरों को जिंदगी का कोई मूल्य नहीं है.

इस दर्दनाक घटना पर जनरल मजदूर लाल झंडा यूनियन (सीटू) के जनरल सेक्रेटरी पूर्णचंद ने मजदूर वर्ग से अपील की कि इस तरह मालिकों के गलत काम को रोकने तथा मजदूरों के जीवन की रक्षा तथा दोषी मालिकों की गिरफ्तारी के लिए सभी मजदूर एकजुट होकर आवाज उठाएं.

सीटू के आह्वान पर 15 मई को कालकाजी पुलिस स्टेशन पर एक प्रदर्शन भी आयोजित किया गया. जिसमें 300 से भी ज्यादा मजदूरोंने भाग लिया.

पटाखों को फैक्ट्री...

[पृष्ठ ग्यारह से आगे]

कैम्प के थे. यह कहा जाता है कि मालिक इन शरणार्थी मजदूरों को ही अधिक नियुक्त करता था क्योंकि वे कम वेतन लेकर भी अधिक मेहनत से काम करते थे.

खान दुर्घटना में तीन मजदूरों की जानें गई

10 मई को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के लैकदीह दीप कोलरी में छत गिर जाने से तीन मजदूरों की जानें गई. दो मजदूरों की घटनास्थल पर मृत्यु हो गयी जबकि एक की मृत्यु रास्ते में ही उसे अस्पताल ले जाते समय हो गई. यह खान बिहार में धनबाद से 30 किमी. दूर है.

खान के गिर जाने से सात मजदूर मारे गए

10 मईको राजस्थान में सिकर जिले के नीलका थाने से 10 किमी. दूर मालीवाड़ा गांव में एक डोलोमाइट खान के गिर जाने से सात मजदूरों की मृत्यु हो गई और लगभग 12 मजदूर घायल हो गए. ये मजदूर खान में काम कर रहे थे.

बम्बई विस्फोट में मिल मजदूरों की मृत्यु

मई 10 की दोपहर में सेंट्रल बम्बई की न्यू प्रभादेवी रोड़ पर स्थित एक कपड़ा मिल में एक मशीन के फट जाने से एक मजदूर की जान गई और नौ घायल हुए. इनमें से दो गंभीर रूप से घायल हुए.

महंगाई के आंकड़े

(आधार 1960-100)

राज्य/केंद्र	1980		
	जन.	फर.	मार्च
बिहार			
जमशेदपुर	359	350	358
झारिया	357	350	357
कोडर्मा	402	399	399
मोंघाइर	396	393	394
नोआमुंडी	388	360	362
गुजरात			
अहमदाबाद	358	357	359
भाव नगर	372	380	387
हरियाणा			
यमुना नगर	393	395	405
जम्मू व काश्मीर			
श्रीनगर	360	361	367
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	385	387	394
भोपाल	368	369	374
ग्वालियर	377	383	392
इंदौर	382	384	387
महाराष्ट्र			
बंबई	376	373	375
नागपुर	368	363	363
शोलापुर	384	381	383
पंजाब			
अमृतसर	388	389	391
राजस्थान			
अजमेर	379	380	385
जयपुर	391	392	392
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	366	368	370
सहारनपुर	375	377	383
वाराणसी	412	423	432
पश्चिम बंगाल			
आसन सोल	379	379	387
कलकत्ता	357	348	356
दार्जीलिंग	308	313	312
हावड़ा	345	340	347
जलपाइगुरी	307	309	312
रानीगंज	370	367	373
दिल्ली	396	393	398
भारत	371	369	373

(लेबर ब्यूरो, शिमला)*

रेलकर्मियों द्वारा दमन के खिलाफ विरोध

रेलवे पुलिस द्वारा एक स्टीममैन, फ्रांसिस को गिरफ्तार किए जाने और तंग किए जाने के खिलाफ 9 मई को विजयवाड़ा लोकोशेड के मजदूरों ने टूल डाउन हड़ताल कर दी. किसी इंजन के एक पुर्जे की चोरी के बारे में फ्रांसिस को रेलवे पुलिस आफिस पूछताछ के लिए ले जाया गया था जहां उसको बुरी तरह पीटा गया. मजदूरों ने मांग की कि फ्रांसिस को लोकोशेड लाए जाने के बाद ही काम शुरू किया जाएगा. इस एकजुट प्रतिरोध के बाद ही रेलवे अधिकारियों ने पुलिस स्टाफ को कहा कि वे फ्रांसिस को वापस भेजें. बुरी तरह पीटे जाने के कारण वह लोकोशेड पहुंचने पर बेहोश हो गया उसके शरीर पर काले और नीले निशान साफ जाहिर थे. जिसके कारण कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी और इसमें कैरिज और इंजीनियरिंग विभाग के कर्मियों ने भी भाग लिया. सवेरे आठ जे से सभी रेल सेवाएं बंद हो गई. दोपहर बाद लगभग दो बजे डिविजनल रेलवे मैनेजर ने संघर्ष के नेताओं से बातचीत की और पुलिस स्टाफ को गिरफ्तार करने की मांग स्वीकार की. उसने यह भी आश्वासन दिया कि वह रेलवे बोर्ड को यह सिफारिश करेगा कि मजदूरों का वेतन नहीं काटा जाना चाहिए. साउथ सेंट्रल रेलवे एंप्लाईज यूनियन (सीटू) ने संघर्ष का पूरा साथ दिया.

सभाएं और सम्मेलन

साउथ सेंट्रल रेलवे एंप्लाईज यूनियन (सीटू) का चौथा सम्मेलन 25-27 अप्रैल को विजयवाड़ा रेलवे इंस्टीच्यूट में संपन्न हुआ. अधिकारियों ने ठीक सम्मेलन के समय पर आयोजन की इजाजत वापस लेनी चाही. समर मुखर्जी, एम. पी., ने हस्तक्षेप किया. उन्होंने 25 अप्रैल को सम्मेलन का उद्घाटन किया. सम्मेलन में पी. सीरामलु, अध्यक्ष और एम. वी. सबैय्याह जनरल सेक्रेटरी सहित 30 सदस्यीय कमेटी चुनी गई. कई प्रस्ताव भी अपनाए गए.

आल इंडिया रेलवे कमर्शल क्लर्क एसोसिएशन की सालाना मीटिंग 26-27 अप्रैल को सिलीगुड़ी में हुई. एम. एन. दास गुप्ता पुनः जनरल सेक्रेटरी चुने गए. खुले अधिवेशन को अन्यों के अलावा समर मुखर्जी, एम. पी., ने संबोधित किया.

आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की आठवीं सालाना मीटिंग 29-30 अप्रैल और 1 मई को आगरा में संपन्न हुई. इसमें 4200 डेलीगेटों और 1 000 प्रेक्षकों ने भाग लिया. बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद एम. आर. सभापति ने, जिन्होंने नवंबर 79 में इस्तीफा दे दिया था, अपना इस्तीफा वापस लेने व अध्यक्षता करने से इंकार कर दिया. लेकिन भूतपूर्व अध्यक्ष के नाते उन्होंने 29 अप्रैल को ध्वज फहराया. मीटिंग के दौरान धूल भरी आंधी से पांडाल गिर पड़ा लेकिन डेलीगेटों ने इसका सामना किया और मीटिंग शांतिपूर्वक चलती रही. रुकावटें पैदा करने की कोशिशें भी एकजुट होकर नाकामयाब कर दी गई. मीटिंग में सर्वसम्मति से के. राजन्ना प्रेजीडेंट और एस. के. धर सेक्रेटरी जनरल चुने गए. मीटिंग में एक प्रस्ताव पारित किया गया. जिसमें कहा गया कि यदि रनिंग अलाउंस कमेटी की रिपोर्ट एक महीने के भीतर नहीं की गई तो संघर्ष शुरू किया जाएगा. एक दूसरे प्रस्ताव में सभी गैर मान्यता प्राप्त यूनियनों व एसोसिएशनों का आह्वान किया गया कि वे एकजुट होकर संघर्ष करें. आगरा छावनी में एक मई को जुलूस और रैली आयोजित की गई जिसे, अध्यक्ष, सेक्रेटरी जनरल और अन्यों के अलावा सीटू सेक्रेटरी नृसिंह चक्रवर्ती ने संबोधित किया.

आल इंडिया गार्ड्स काउंसिल की सालाना मीटिंग 26-27 अप्रैल को लखनऊ में संपन्न हुई. सी. एल. उपाध्याय पुन: जनरल सेक्रेटरी चुने गए.

इंडियन रेलवेज सिगनल व टेलिकाम स्टाफ एसोसिएशन की सालाना मीटिंग हरिद्वार में 11-12 मई को हुई. करीब 2,000 डेलीगेटों और प्रेक्षकों ने इसमें भाग लिया. एन. एस. भंगू पुनः इसके अध्यक्ष चुने गए.

रनिंग अलाउंस कमेटी की रिपोर्ट

रनिंग अलाउंस कमेटी की रिपोर्ट, जिसे 3 अप्रैल को दाखिल किया गया था, 15 मई को प्रकाशित की गई. रिपोर्ट की समीक्षा अगले अंक में दी जाएगी. लेकिन यह बताना जरूरी है कि यह रिपोर्ट 5-6 सालों से चले आ रहे रेलवे मंत्रालय के इस प्रचार का, कि रनिंग स्टाफ का औसत वेतन रेलवे मजदूरों के दूसरे हिस्सों के वेतन से ज्यादा हैं, भंडाफोड़ करती है.

भारतीय केटरिंग सेवा

सुप्रीम कोर्ट का फैसला (मई 1980 अंक) असलियत में रेलवे मंत्रालय को भारतीय केटरिंग सेवा स्थापित करने का निर्देश देते हुए एक अंतरिम आदेश था, ताकि रेलवे कर्मचारियों को अच्छा खाना दिया जा सके. इस प्रकार हाई कोर्ट के फैसले जिसमें कैंटीनों के कर्मचारियों को रेलवे कर्मचारी घोषित किया गया था, के खिलाफ मंत्रालय की अपील ने नया मोड़ ले लिया है. कैंटीन एंप्लाईज फेडरेशन के अध्यक्ष एच. के. बनर्जी जुलाई के तीसरे सप्ताह में दिल्ली में एक कनवेंशन आयोजित कर रहे हैं ताकि रेलवे कैंटीनों व प्राइवेट रेस्तरांओं के कर्मचारियों, वेंडरों और कमीशन वियररों के आंदोलन की तालमेल की जा सके.

सीटू मजदूर

सी आई टी यू का मासिक मुखपत्र

एक प्रति की दर — पचास पैसे

वार्षिक चंदा — छः रुपये

मिलने का पता :

सीटू कार्यालय

6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001

फोन : 384071

पश्चिम बंगाल समाचार

सी. टी. ए. का 12वां सम्मेलन

कमर्शल ट्रेवलर्ज एसोसिएशन (सी. टी. ए.), पश्चिम बंगाल, का 12वां सालाना सम्मेलन 26-27 अप्रैल को कलकत्ता में सम्पन्न हुआ. इसमें 250 डेलीगेटों, बिरादराना डेलीगेटों और प्रेक्षकों ने भाग लिया. ज्योति बसु और कृष्णपद घोष ने संदेश भेजे. सुनिल मोइत्रा, एम. पी. ने खुले अधिवेशन का अनावरण किया. मुहम्मद अमीन ने सोवेनियर का अनावरण किया. अपने अध्यक्षीय भाषण में, जी दत्ता ने तानाशाही ताकतों से पैदा हुए खतरे, भारतीय उपमहाद्वीप और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में साम्राज्यवादी षड्यंत्रों और बढ़ती हुई कीमतों आदि के बारे में चेतावनी दी.

जनरल सेक्रेटरी की रिपोर्ट संशोधन के बाद स्वीकार कर ली गई. सम्मेलन ने एक एक्जीक्यूटिव कमेटी चुनी. जे. दत्ता अध्यक्ष और एस. आर. राय जनरल सेक्रेटरी चुने गए, दोनों ही दिन दिल्ली के जन नाट्य मंच ने नुक्कड़ नाटक किये जिनकी काफी प्रशंसा की गई.

वन-मजदूरों का 11वां सम्मेलन

दार्जीलिंग डिस्ट्रिक्ट फोरेस्ट मजदूर यूनियन (सीटू) का 11वां विशेष सम्मेलन बाबडोगरा के निकट ताईपू बहारा वन में 10-11 मई को सम्पन्न हुआ. इसमें 100 से भी ज्यादा डेलीगेटों ने भाग लिया. रमाशंकर प्रसाद ने अध्यक्षता की. उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मजदूरों को मौजूदा पूंजीवादी ढांचा बदलने और समाजवादी समाज की स्थापना में अपनी अगुवा भूमिका अदा करनी चाहिए

जनरल सेक्रेटरी. आनंद पाठक, एम. पी. ने अपनी रिपोर्ट में बन मजदूरों का दैनिक वेतन रु० 9.20 करने जो 1969 में मात्र 3 रुपये था, और बागान कार्य के पारिश्रमिक की दर रु. 1,360.00 प्रति हेक्टेयर करने, यह दर 1969 में 75 रुपये प्रति एकड़ थी, के लिए व अन्य सुविधाओं के लिए पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार का धन्यवाद किया. मजदूर वर्ग के फौरी मुद्दों पर प्रस्ताव पास किए गए. सम्मेलन में रमाशंकर प्रसाद, प्रेजीडेंट और आनंद पाठक, जनरल सेक्रेटरी सहित एक नई कार्यकारिणी चुनी गई.

सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन

पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सरकार कर्मचारियों ने बोनस की मांग करते हुए 17 अप्रैल को प्रदर्शन आयोजित किए. उन्होंने कलकत्ता में राजभवन के पास एक रैली आयोजित की और राजभवन कार्यालय में एक मेमोरेंडम भी दाखिल किया.

स्वचालन की सभी योजनाएं खत्म करो

ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में प्रबंधकों द्वारा कंप्यूटर लगाए जाने के खिलाफ कार्यवाही तय करने के लिए बर्दवान जिला में दिशेरगढ़ में सीटू, एटक, उटक एच. एम. एस और इंटक के प्रतिनिधियों की 19 अप्रैल को एक बैठक हुई. बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें ई. सी. एल. के प्रबंधकों की पिछले कई सालों से इलेक्ट्रानिक कंप्यूटर लगाने की कोशिशों पर चिंता व्यक्त की गई. बैठक में सभी कामगारों व ट्रेड यूनियनों का स्वचालन के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान चलाने का आह्वान किया गया ताकि नौकरी सुरक्षा रोजगार और निर्वाह के स्तर पर इस नए हमले को करारी शिकस्त दी जा सके. बैठक में कोलियरियों, एरिया दफ्तरों, एजेंट दफ्तरों और मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का भी फैसला किया. स्वचालन के खिलाफ क्षेत्रानुसार सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे.

प्रगतिवादी ताकतें एक होकर संघर्ष करें

तेल मजदूरों के पांचवे इजारेदार-विरोधी सम्मेलन ने विश्व की सभी प्रगतिशील शक्तियों को एक होकर तेल इजारेदारों के खिलाफ संघर्ष छेड़ने का आह्वान किया है. यह सम्मेलन तेल-मजदूरों की इजारेदार-विरोधी स्थायी-समिति ने लिबिया के जनरल ट्रेड यूनियन आफ पैट्रोलियम, पैट्रो-केमिकल और खान मजदूरों के निमंत्रण पर 26 से 30 मार्च तक त्रिपोली (लिबिया) में बुलाया था.

इस सम्मेलन में 56 देशों से 250 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें तेल और उससे संबंधित मजदूरों की 54 ट्रेड यूनियनों के नुमाइंदे थे और डब्ल्यू. एफ. टी. यू., आई. एल. ओ., टी. यू. आई. आफ आयल., केमिकल और संबंधित उद्योगों सहित 6 अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के नुमाइंदों ने, टी. यू. आई. आफ ट्रांसपोर्ट वर्कर्स तथा राष्ट्रीय मुक्ति और जनवादी संगठनों के 44 प्रतिनिधि मंडलों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया. इस सम्मेलन में भारत से आल इंडिया केमिकल और फार्मेस्यूटिकल फेडरेशन की तरफ से जे. एस. मजूमदार ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए विश्वस्तर पर एक अभियान छेड़ने के आह्वान की जरुरत पर जोर दिया ताकि मजदूर वर्ग के व्यापक हिस्सों को इसमें शामिल किया जा सके.

बहस में 'तेल इजारेदारों के अपने प्रभुत्व कायम रखने और अपने मोटे मुनाफों को लगातार बढ़ाते जाने की कोशिशों पर विचार-विमर्श के साथ-साथ सम्मेलन ने विकसित पूंजीवादी देशों तथा तेल का उत्पादन करने वाले और तेल का उत्पादन न करने वाले देशों के तेल-मजदूरों के संघर्षों और सफलताओं की भी समीक्षा की. औद्योगिक पूंजीवादी देशों के तथा साम्राज्यवाद और नव-उपनिवेशवाद से जो विकासशील देश अभी मुक्त नहीं हुए हैं, के तेल मजदूरों ने अपने कड़े संघर्षों और हड़तालों के बाद जो सफलताएं प्राप्त की हैं उन पर भी इस सम्मेलन में प्रकाश डाला गया. यह भी नोट किया गया कि समाजवादी देशों और बहुराष्ट्रीय पेट्रोलियम संस्थानों

[शेष पृष्ठ पंद्रह पर]

वस्त्र उद्योग के श्रमिक हड़ताल पर

पूरे मद्रास में वस्त्र उद्योग में 20,000 से अधिक मजदूर काम करते हैं. इनमें से अधिकतर महिलाएं हैं और यह उद्योग अधिकतर निर्यात करता है. लगभग सभी कपड़ा इकाइयों में मजदूरों को असामान्य रूप से बहुत कम वेतन दिया जाता है. इन महिला मजदूरों के साथ बुरा व्यवहार कर इन्हें सताया भी जाता है. उन्हें गैर-इन्सानी हालात में काम करना पड़ता है और वहां प्रबंधक कोई मजदूर कल्याण कानून लागू नहीं करते.

एक इकाई को बंद कर दूसरी को नए नाम और अलग निर्यात आर्डरों के साथ खोलना इस उद्योग का एक नियमित काम बन गया है. वह सब मजदूरों में बढ़ रही एकता को तोड़ने के लिए किया जाता है. जब एक संस्था अपना नाम बदल लेती है तो उसमें काम कर रहे सभी मजदूर खुद-ब-खुद नौकरी से बरखास्त हो जाते हैं और इस प्रकार बेरोजगार हो जाते हैं.

इसका एक उदाहरण मैलापोर का 'बालू एक्सपोर्ट्स' है जो बालू गारमेन्ट्स, रासी सिल्क, रासी एक्सपोर्ट्स, राधा सिल्क आदि विभिन्न नामों के तहत चलाया गया. हालांकि प्रबंधकों ने 500 से अधिक महिलाओं को नियुक्त किया पर यहां किसी प्रकार का मजदूर कानून लागू नहीं किया गया. प्रति माह अधिक से अधिक 70 से 100 रुपये तक है. मजदूरों की यूनियन बन जाने के बाद प्रबंधकों ने जनवरी में 42 मजदूरों को और बाद में 93 मजदूरों को निकाल दिया. जब इसका विरोध किया गया तो प्रबंधकों ने फैक्टरी ही बंद कर डाली. महिला मजदूर जो दूर-दूर से आई थीं और यहां होस्टलों में रह रही थीं उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.

राजन इंटर कोन्टिनेन्टल ने 119 मजदूरों को जिनमें अधिकतर महिलाएं थीं 3 रु० प्रतिदिन देकर काम करवाया. फरवरी में जब ये मजदूर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए यूनियन के सदस्य बने तो इनकी छटनी कर दी गई और उन्हें इसका मुआवजा भी नहीं दिया गया. भूख से पीड़ित मजदूरों की नौकरियां छीन कर उन्हें झुकने के लिए मजबूर करने का वह कदम जान-बूझ कर उठाया गया था. यही हाल अन्य गारमेंट्स फेक्टरियों का भी है.

राज्य सीटू कपड़ा मजदूरों को संगठित कर रही है और कपड़ा मजदूरों के समर्थन में एक मिलाजुला आंदोलन करने की कोशिश कर रही है. 21 मार्च को 500 महिलाओं सहित 1000 मजदूरों ने राज्य सचिवालय तक मार्च किया और राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया. तमिलनाडु डेमोक्रेटिक वुमेंस फेडरेशन और वर्किंग वूमेंस काउन्सिल ने अपनी इकाइयों को संघर्षरत कपड़ा मजदूरों के समर्थन में एक आंदोलन करने का आह्वान किया हैं.

बिहार
ग्लेक्सको की चीजों का बायकाट

आल इंडिया केमिकल एंड फार्मेस्यूटिकल एंप्लाईज फेडरेशन (ए.आई.सी.ए.पी.ई.एफ.) और फेडरेशन आफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्ज एसोसिएशन आफ इंडिया (एफ.एम.आर.ए.आई.) का दवा उद्योग की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ संघर्ष अब भारत में सबसे बड़ी कंपनी ग्लेक्सो के खिलाफ केंद्रित किया जा रहा है. दोनों संगठनों ने अब समूचे देश में ग्लेक्सो की बनी चीजों का बायकाट करने का अभियान शुरू कर दिया है और बिहार में 30 मार्च से 12 अप्रैल तक संघर्ष कार्यवाही की गई.

राज्य के सभी जिलों में पोस्टर लगाए गए, पर्चे बांटे गए. अनेक गेट सभाएं व नुक्कड़ सभाएं की गईं. इसके अलावा डाक्टरों से भी भेंट की गई. बिहार स्टेट सेल्स रिप्रजेंटेटिव्ज यूनियन के सदस्यों द्वारा सभी जिला अधिकारियों को स्मरण-पत्र दिए गए ताकि वे केंद्रीय सरकार के पास भेजे सकें. पटना में 12 अप्रैल को एक रैली आयोजित की गई. ए.आई.सी.पी.ई.एफ. की बिहार शाखा की सीटू एटक व अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ हुई बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें ग्लेक्सो विरोधी संघर्ष के द्वारा समर्थन दिया गया.

विश्व ट्रेड यूनियन सम्मेलन

[पृष्ठ चौदह से आगे]

के शिकंजे से मुक्त हो चुके तेल उत्पादक देशों में मजदूरों के काम करने और रहने की परिस्थितियों में काफी और स्थायी सुधार हुआ.

सम्मेलन में बहुराष्ट्रीय निगमों के नियंत्रण को समाप्त करने तथा सच्चे सहयोग और तकनीकी ज्ञान के आदान-प्रदान को हासिल करने के लिए आयल ट्रेड यूनियनों द्वारा आवश्यक एकजुटता की कार्यवाहियां करने और उनकी प्रवृति तथा भूमिका पर भी विचार-विमर्श किया गया. सम्मेलन ने इस दिशा में कुछ ठोस सुझाव दिए और तमाम ट्रेड यूनियनों का आह्वान किया कि वे तेल मजदूरों, राष्ट्रीय-मुक्ति-संग्रामों तथा संघर्षरत जनता के साथ एकजुट होकर दमन और शोषण, उपनिवेशवादी और नवउपनिवेशवादी प्रभुत्व, रंगभेद, नियोनिज्म और साम्राज्यवाद के खिलाफ संयुक्त संघर्ष करें.

भारत के औद्योगिक विवाद

[पृष्ठ छः से आगे]

समय का नुकसान हड़तालों के कारण नुकसान से ज्यादा पाया गया है. 1977 और 1978 के आंकड़े यह बताते हैं. कि 1978 में जहां हड़तालों के कारण समय का हानि 1977 से 8.5% ज्यादा रही वहां तालाबंदियों के कारण इसी दौरान यह वृद्धि 15% थी. सारिणी II में इन दो सालों के लिए प्रति हड़ताल और प्रति तालाबंदी मनुष्य-दिनों में समय की हानि दी गई है.

विभिन्न राज्यों में 1977 और 1078 में हड़तालों और तालाबंदियों के कारण औद्योगिक विवादों की संख्या, इनसे प्रभावित मजदूरों की संख्या और कुल मनुष्य दिनों की हानि सारिणी III में दी गई है.

तमिलनाडु

राज्य सरकार कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त

स्टेट ट्रेजरी डिपार्टमेंट के 2000 से अधिक कर्मचारियों ने 28 मार्च को अपने सात सूत्री मांग पत्र के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी. इस मांगपत्र में कार्यभार अधिक हो जाने के कारण अधिक नियुक्तियों, वेतनमानों में असमानता खत्म करने तथा प्रमोशन आदि की मांग की गई थी. यह हड़ताल चार दिनों के बाद तब समाप्त कर दी गई जब सरकार ने इनकी कुछ मांगें मंजूर कर ली तथा कुछ पर बाद में विचार करने का आश्वासन दिया.

ध्यान रहे कि हड़ताल के दौरान ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अन्य विभागों के कर्मचारियों ने आदेशों के बावजूद काम करने से मना कर दिया. सीटू की राज्य कमेटी ने कर्मचारियों को उनके एकजुट संघर्ष और समझौते के इस कदम पर बधाई दी है.

कीमत-वृद्धि और विक्टिमाइ-जेशन के खिलाफ प्रदर्शन

सीटू की मद्रास चिंगलेपेत कमेटी के आह्वान पर 500 महिला मजदूरों सहित 5000 से अधिक मजदूरों ने तमिलनाडु राज्य सचिवालय तक मार्च किया. ये मजदूर, कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ, बिजली की कटौती के कारण काटे गए वेतन की मांग के लिए तथा बंद हुई फैक्टरियों को दोबारा खोलने, विक्टि-माइजेशन का खात्मा और ट्रेड यूनियन अधिकारों की हिफाजत के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे थे.

संपादक मंडल

बी. टी. रणदिवे (अध्यक्ष)

पी. राममूर्ति मनोरंजन राय

निरेन घोष सुधिन कुमार

एम. के. पंधे (संपादक)

बैंक इजारेदार...

[मुखपृष्ठ से आगे]

यह मुख्य समझौते का ही हिस्सा हो."

इस बारे में यह बात नोट करने की है कि कोयला समझौते की पूर्व संध्या को प्रबंधकों ने कुछ मांगें उठाने की कोशिश की लेकिन सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने इनकी ओर ध्यान देने से इंकार कर दिया. कुछ अन्य सार्वजनिक उद्योगों में भी ट्रेड यूनियनों ने यही कदम उठाया. ए.आई.बी.ई.ए. के इस कदम ने एक बुरा उदाहरण स्थापित किया है जो केवल अन्य उद्योगों में प्रबंधकों को मजदूरों और कर्मचारियों के खिलाफ प्रति-मांगें उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगा तथा द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय वार्ताओं को बेकार करेगा.

इस समझौते का दूसरा हानिकारक पहलू यह है कि मध्यस्थता करनेवालों का बहुमत भी दोनों पार्टियों को मानना होगा. इसका मतलब यह है कि मध्यस्थता करने वाले 3 व्यक्तियों में यदि बैंकरों का नुमाइंदा और न्यायाधिकारी यदि मशीनीकरण में वृद्धि के लिए सहमत होते हैं तो यह कर्मचारियों को मानना ही पड़ेगा.

आश्चर्य की बात यह है कि हाल ही के समझौते के बाद ए.आई.बी.ई.ए. के नेतृत्व ने प्रबंधकों द्वारा उठाई गई मांगों के खिलाफ कोई भी गंभीर आंदोलन नहीं छेड़ा है. यदि ऐसा कोई आह्वान किया जाता तो हमें पूरा यकीन है कि बैंक कर्मचारी अवश्य ही संघर्ष करते.

हम आशा करते हैं कि बैंक कर्मचारी इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करेंगे क्योंकि ये न केवल बैंक कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है बल्कि यह हमारे देश के समूचे मजदूर वर्ग के हितों के खिलाफ है.

कामरेड जोसिप ब्रोज टीटो

सोशलिस्ट फेडरल रिपब्लिक आफ यूगोस्लाविया के प्रेजीडेंट और लीग आफ कम्युनिस्ट्स आफ यूगोस्लाविया के प्रेजीडेंट, कामरेड जोसिप ब्रोज टीटो का 4 मई को लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया. वह 85 वर्ष के थे.

कामरेड टीटो ने, जो व्यवसाय से धातु मजदूर थे, इटली और जर्मनी ताकतों के खिलाफ फासीवाद विरोधी संघर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की. कई सालों तक गौरवशाली हथियारबंद संघर्ष के बाद कामरेड टीटो ने यूगोस्लाविया की जनता का फासीवाद पर विजय के लिए मार्गदर्शन किया.

स्वतंत्रता के बाद कामरेड टीटो ने विश्वशांति के लिए संघर्ष में ख्यातिपूर्ण कार्य किया और निर्गुट आंदोलन के संस्थापकों में से एक बने. कामरेड टीटो भारत की जनता के साथ दोस्ताना संबंधों को बढ़ाने के लिए सदैव रूचि लेते थे.

उनकी मृत्यु से विश्व ने इस समय का एक महान राजनीतिज्ञ खो दिया है.

सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंज और सीटू मजदूर यूगोस्लाविया की काउंसिल आफ कनफेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंज को और यूगोस्लाविया के मजदूर वर्ग व जनता को उनके प्रिय नेता की बिदाई पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजती है.

सीटू की ओर से यूगोस्लाविया के दूतावास में 6 मई को सीटू के सचिव एम. के. पंधे व नृसिंह चक्रवर्ती तथा सीटू के केंद्रीय कार्यालय के स्टाफ के अन्य सदस्यों ने श्रद्धांजलि अर्पित की.

इस्पात के लिए नेशनल ज्वाइंट कमेटी ने अपनी 5 मई की बैठक में कामरेड टीटो की याद में श्रद्धांजलि अर्पित की.

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्ज के लिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071) से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, 97-98, डीएसआईडीसी कम्पलैक्स, ओखला, फेज-II, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित